



जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हुआ और मंगलवार दूसरे दिन भी जोधपुर का आसमान फाइटर प्लेनों की आवाजों से गुंजायमान रहा। अमेरिका निर्मित शक्तिशाली एफ-16 फाइटर जेट भी पहली बार जोधपुर के आसमान में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई-30 ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। पहले दिन आपसी तालमेल बैठाने के अलावा आसमान में काल्पनिक टारगेट्स को हिट कर दोनों एयरफोर्स के जांबाज पायलट्स ने युद्ध कौशल दिखाया। भारत और ओमान की वायुसेना के इस साझा युद्धाभ्यास के दौरान हवा में ही टारगेट्स को निशाना बनाना सिखाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट दुश्मन के फाइटर जेट को घेरकर नीचे उतारना भी सीख रहे हैं।

# क्या बजट में कांग्रेस सरकार कर सकती है नए जिले की घोषणा

## महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने तीनों कार्यकाल में अशोक गहलोत ने एक भी नया जिला नहीं बनाया है

जयपुर, 22 फरवरी (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इस बार राजस्थान में एक नई शुरुआत करते हुए कृषि के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। अतः किसानों को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इससे भी बढ़कर उत्सुकता इस बात को लेकर है कि इस बजट में राजनीतिक संदेश क्या होगा।

और यह भी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायकों की मांग को देखते हुए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं और इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। हालांकि जिलों की घोषणा बहुत बड़ा राजनीतिक मामला होता है। ऐसे में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में क्या ऐसा होने वाला है। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में पिछले 30-

26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था, उसके बाद से कई जगह से उठती रही है मांग।

35 साल में जितने भी नए जिले बनाए गए हैं। उनकी घोषणा भाजपा शासनकाल में ही हुई है और अंतिम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था, जिसकी घोषणा भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी।

वैसे तो राजस्थान में कई जिले नए बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन जहां आवश्यकता समझी जा रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं- बाड़मेर का बालोतरा, जोधपुर का फलोदी, सीकर का नीमकाथाना और अजमेर का ब्यावर थो। ऐसी तहसीलें हैं, जहां जिले बनाए जाना बेहद आवश्यक

माना जा रहा है, क्योंकि इन सभी तहसीलों को जिला मुख्यालयों से दूरी 80 से 100 किलोमीटर तक है। यही कारण है कि बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत की यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता है, तो वे कभी भी जूते नहीं पहनेंगे और हमेशा नंगे पांव रहेंगे। इसे

लेकर अब सरकार पर भी दबाव है। नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग करीब 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हो रही है। इसी लाइन में जयपुर जिले का कोटपली भी है। इसी तरह ब्यावर को जिला बनाने की मांग करीब 30 साल पुरानी है, तो फलोदी को जिला बनाने की मांग भी 25-30 साल से लगातार उठ रही है।

### लिखित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे कि वे शीघ्रता के लिहाज से अपनी दलीलें न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर, दिनेश मोहनशरी तथा सी.टी. रवि कुमार की बैच बुधवार को त्वरित सुनवाई के लिये राजी हो गई तथा बैच ने वकील को निर्देश दिये कि वे याचिका की एक अग्रिम गति सी.बी.एस.ई. तथा अन्य प्रतिवादिनों को पहुँचा दें। याचिका में मांग की गई है कि सी.बी.एस.ई. तथा अन्य शिक्षा बोर्डों, जिन्होंने कक्षा-10 तथा 12 की बोर्ड परीक्षाएँ ऑफ लाइन प्रस्तावित कर दी हैं, को निर्देश दिये जायें कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के अन्य तरीके (मोड) अपनाये जायें। सी.बी.एस.ई. 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएँ कराने का निर्णय पहले ही ले चुका है।

### नीतीश कुमार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब तक कि वे (नीतीश कुमार) भाजपा से अपने संबंध ना तोड़ लें। पहले उन्हें भाजपा से संबंध विच्छेद करने होंगे तथा इसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियाँ एक जगह बैठकर इस पर विचार करेंगी। बिहार में, वर्तमान में भाजपा के सहयोग वाली जे.डी. (यू.) सरकार है। मलिक ने भाजपा पर आरोप लगाया

कि जब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार थी तब उसने वर्ष 1993 में साम्प्रदायिक दंगे करवाये थे और वहाँ के लोगों ने उसी वजह से उसे सत्ता से बाहर किया था। एन.सी.पी. नेता ने कहा कि अगले महीने जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएँ तब उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष बाद इतिहास अपने आगोके दोहराएगा। मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता 25 वर्ष बाद वर्ष 2017 में भाजपा को सत्ता में लेकर आयी। यहाँ के लोग पिछले पाँच वर्षों के दौरान उसकी राजनीति से तंग आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में 150 से कम सीटें मिलेंगी। तथापि, भाजपा वास्तविकताओं से परे यह उम्मीद कर रही है कि लोक सभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में वह अपनी सरकार बनाने में किसी तरह कामयाब हो जाएगी और यह संभव करने के लिए वह जी-तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सत्ता में वापसी की संभावनाओं से इंकार किया जा रहा है क्योंकि आक्रामक सपा विरुद्ध वह काफी मुश्किल में फंसी हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस और बसपा भी भाजपा के वोटों में संघमारी कर रहे हैं।

### कब क्या हुआ:

-20 जुलाई 2021 को आयोग ने आर.ए.एस. के 363 और अधीनस्थ सेवाओं के 625 पदों पर भर्ती निकाली।

-27 अक्टूबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई।

-3 नवंबर 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई।

-19 नवंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी।

-22 नवंबर 2021 को आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी।

# आर.ए.एस. भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द

## 25-26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा के आयोजन में देरी होने की संभावना

जयपुर, 22 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आर.ए.एस. भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी से जुड़े विवाद को लेकर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मॉडल प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 41 को डिलीट करते हुए सवाल संख्या 1, 31, 98 और 105 का पुनः परीक्षण करने के निर्देश देते हुए इन्हें विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष भेजा है। वहीं अदालत ने प्रश्न संख्या 62 में आयोग की ओर से सही माने गए विकल्प संख्या तीन को बदलते हुए सही जवाब विकल्प संख्या एक माना है। जस्टिस मेहनद्र गौयल की एकलपीठ ने यह आदेश अंतिम कुमार शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर.ए.एस. मेन्स की 25-26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा के आयोजन में देरी होने की संभावना है। आर.पी.एस.सी. के अधिवक्ता अमित लुभाया का कहना है कि फिलहाल आदेश का परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद ही अपील करने को लेकर

■ हाईकोर्ट ने कुछ प्रश्नों को पुनः परीक्षण के लिये विशेषज्ञ कमेटी को भेजा है।

निर्णय किया जाएगा। यदि आयोग की ओर से खंडपीठ में अपील की जाती है और वहां एकलपीठ के आदेश पर रोक लगती है तो आयोग को मुख्य परीक्षा को लेकर राहत मिल सकती है। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व अन्य ने बताया कि आयोग की ओर से आर.ए.एस. भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गईं और याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां पेश कर दीं। इसके बाद आयोग ने आपत्तियों का निपटारा करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी भी निकाल दी। याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने कुछ सवालों के जवाब गलत जांचे हैं। इसके अलावा एक सवाल के एक से

अधिक उत्तर भी सही हैं। याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों के जवाब पेश करते हुए कहा गया कि उनकी ओर से किए गए सवालों को सही माना जाए। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित लुभाया ने अदालत को बताया कि मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने के बाद नियमानुसार आपत्तियां मांग कर उसका निस्तारण किया गया था और विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम जारी कर अंतिम उत्तर कुंजी निकाली गई थी। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा परिणाम रद्द करते हुए चार विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से कराने, एक प्रश्न का विकल्प बदलने और एक प्रश्न को डिलीट करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि विपक्षी विचारकों और अभ्यर्थियों की ओर से आरएएस मेन्स परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ही कहा था कि मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी। उन्होंने परीक्षा

स्थगित करने की मांग को गलत ठहराया था। साथ ही कहा था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ और भर्तियाँ तय समय में पूरी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके मुताबिक परीक्षाएँ करवा रहा है। गहलोत ने आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा भी 25 और 26 फरवरी को आर.पी.एस. सी. के कैलेंडर के मुताबिक करवाने की बात कही थी।

### कब क्या हुआ:

-20 जुलाई 2021 को आयोग ने आर.ए.एस. के 363 और अधीनस्थ सेवाओं के 625 पदों पर भर्ती निकाली।

-27 अक्टूबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई।

-3 नवंबर 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई।

-19 नवंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी।

-22 नवंबर 2021 को आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी।

# पुतिन ने सेना को पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश दिया

माँस्को, 22 फरवरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क भेजने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक इन इलाकों में पहुँच चुके हैं। इससे पहले पुतिन ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्रता देश को मान्यता दी थी। यहाँ कुछ कंपनियों के शेरयर लगातार गिरते जा रहे हैं। उधर, पुतिन के आदेश पर पश्चिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों को स्वतंत्र पूर्वी यूक्रेन के रूप में मान्यता देने के बाद सेना भेज दी है। यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क-डोनेट्स्क में रूसी सेना के टैंक इस क्षेत्र में घुस गए हैं। हालांकि रूसी सैनिक भेजे जाने के सवाल पर पुतिन ने जवाब दिया है कि

■ इससे तुरन्त पहले राष्ट्रपति पुतिन ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी कर दी थी।

अलगाववादियों के कब्जे वाले दोनों प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पुतिन के अपने सैनिकों को इन क्षेत्रों में भेजने के आदेश पर से बैंक जैसी कंपनियों के शेरयर तेजी से गिर गए हैं।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में मध्य डोनेट्स्क में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। संभावना जताई जा रही है

कि रूसी सैनिकों के इन इलाकों में घुसने के बाद यहाँ संघर्ष की कुछ घटनाएँ सामने आई हैं।

वहीं, पुतिन के इस कदम पर पश्चिमी नेताओं ने चेतावनी दी है कि उन्हें इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पुतिन के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी नेताओं ने निंदा की है।

यूक्रेन पर संकट के बीच तमाम देशों ने रूस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पहले जर्मनी ने रूस के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नोर्ड स्ट्रीम को रद्द कर दिया है। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को रूस के पांच बड़े बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। बोरिस ने पुतिन पर यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

# चुनावी रैलियों और प्रचार पर हर प्रकार की लिमिट खत्म हुई

## चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की

■ इसी के साथ रैली के लिए 50 प्रतिशत की लिमिट भी अब खत्म हो गई है।

दिल्ली, 22 फरवरी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है। इसी के साथ रैली के लिए 50 प्रतिशत की लिमिट भी अब खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैली पर कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, बीच में ही चुनाव आयोग ने नियमों में

राहत दी थी। -19 मामलों में गिरावट का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया था, जिससे अब सभी पार्टियाँ नियम के मुताबिक पहले जितनी संख्या में स्टार प्रचारकों की मैदान में उतर सकती हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। अन्य पार्टियाँ जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके पास अब

20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार पांच राज्यों में कुल सात चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। इसमें से अब तक तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इसमें चौथे चरण के चुनाव बचे हुए हैं। इसमें चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को, छठवें चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे।

# अरब पैसा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हुये डेटा से यह सामने आ गया है कि इस क्षेत्र, जिसमें राजनेताओं के पैसे के बारे में पारदर्शिता का लम्बे समय से अभाव रहा है, के वर्तमान एवं पूर्व नेताओं ने विदेशी बैंकों में अपार धन जमा कर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दर्शाता है कई देश अपने शासकों और देशों की सम्पत्ति के बीच पृथक्करण सीमा रेखा खींचने में असफल रहा है।

लीक हुए डेटा में एक मात्र वर्तमान राष्ट्रप्यक्ष जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं, जो अमेरिका के बहुत नजदीक हैं तथा जिनके राज्य को अमेरिका से कम से कम 22 अरब डॉलर की सैन्य एवं आर्थिक मदद हासिल हुई है। डेटा के अनुसार अब्दुल्ला के छः स्विस खाते हैं, जिसमें वह खाता भी शामिल है जिसमें 2015 में 22.40 करोड़

डॉलर से ज्यादा धनराशि जमा थी। कुछ वर्ष पूर्व, 2011 में "अरब स्प्रिंग" के जोर पकड़ने के दौरान मिश्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के सत्ता से अपदस्थ होने से पहले, उनके तथा उनके बेटों के नजदीकी व्यक्ति बन्धुओं के छः खाते हैं, जिनमें एक जॉर्डन खाता भी शामिल है, जिसमें 2003 में 19.60 करोड़ डॉलर जमा थे।

लीक यह दर्शाती है कि "क्रैडिट सुईस" बैंक उन लोगों के खाते खोलने तथा उनका खयाल रखने में "रैड फ्लैग्स" की उपेक्षा करने की चूक कर बैठता, जिन लोगों की सम्पत्तियों से भरी पृष्ठभूमि हर उस व्यक्ति के सामने खुली हुई, जो सच ईजन् के जरिये उनके नामों को चलाता था।

# कोरोना की "ऑन लाइन" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जबकि आई.सी.एम.आर. ने किसी भी "ऑन लाइन एप्रोगेटर" कम्पनी को करीना की जांच करने के लिए मान्यता नहीं दी थी।

उन्होंने अदालत को बताया कि क्योंकि इन "एप्रोगेटरों" को आई.सी.एम.आर. ने या एन.ए.बी.एल. ने प्रमाणित नहीं किया है, इस वजह से यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि क्या इन कम्पनियों में कोरोना की जांच के लिए किए जा रहे टैस्ट के लिए योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सैम्पल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कम्पनियों के कार्यप्रणाली पर और भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि, क्या सैम्पल कलैक्शन के बाद उसे सही जगह और तरीके से स्टोर किया जा रहा है? क्या सैम्पल कलैक्शन के बाद इसे सही समय सैम्पलों में लैब में टैस्ट के लिए पहुंचाया जाता है? क्या सैम्पल का टैस्ट योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में किया जाता है? और क्या सही समय पर टैस्ट की रिपोर्ट यथा समय प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई

करते हुए 14 फरवरी को आदेश दिये थे, परन्तु 21 फरवरी की शाम तक ही न्यायाधीश द्वारा एप्रोगेटर्स आदेश को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आई.सी.एम.आर. को "ऑनलाइन एप्रोगेटर्स" के मानक तय कर एक हफ्ते में वैबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिये गए हैं। इस आदेश के बाद जब अधिवक्ता शशांक देव सुधि से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दरअसल "ऑन लाइन" एप्रोगेटर्स" के संचालन का निरीक्षण करने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि स्वास्थ्य राज्यों की सूची का विषय है, परन्तु राज्यों का कहना है कि क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान "डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट" लागू किया गया था, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। सभी सरकारें और विभाग एक दूसरे पर दबावरोपण कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पूछा गया था कि किस "ऑन लाइन एप्रोगेटर" के खिलाफ किसी भी राज्य में कोई कार्यवाही की गयी थी और इस कार्यवाही का

क्या कोई "एक्शन रिपोर्ट" दर्ज की गई है, "तब केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से इन कम्पनियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें आई.सी.एम.आर. को "ऑनलाइन एप्रोगेटर्स" के मानक तय कर एक हफ्ते में वैबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिये गए हैं। इस आदेश के बाद जब अधिवक्ता शशांक देव सुधि से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आई.सी.एम.आर. और एन.ए.बी.एल. जैसी संस्था केवल मैडिकल लैब द्वारा लिये जा रहे टैस्ट को ही प्रमाणित करती हैं, उनके पास किसी लैब के खिलाफ कार्यवाही करने के कोई अधिकार नहीं है यह केवल राज्य या केन्द्र सरकार के पास है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आई.सी.एम.आर. को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर "ऑन लाइन एप्रोगेटर्स" के द्वारा किये जा रहे टैस्ट के मानक तय करने के आदेश दिये हैं, और मामले की अगली तारीख 9 मई तय की है। शशांक देव सुधि का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक आदेश है क्योंकि ऐसे आदेश की कोई इसको मिसाल नहीं है। इस आदेश से पूरे देश में कार्यरत "ऑन लाइन एप्रोगेटर" कम्पनियों को रूगलेट और मॉनिटर किया जाएगा।

दुनिया ठीक उसका उल्टा सोचती है और रूस की कार्यवाहियाँ स्वयं के खिलाफ अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को आमंत्रित कर रही हैं। एक तरह से पुतिन ने ऐसा कर कुछ उन देशों को भी स्वयं से दूर कर दिया है जो उसके लिए कूटनीतिक वार्ताओं के कुछ अवसर उपलब्ध करवा रहे थे।

इसके साथ ही जर्मनी ने रूस से मध्य यूरोप तक जा रही नॉर्ड स्ट्रीम-2, पाइप लाइन में नैचुरल गैस की जरूरी सप्लाई रोक दी है। इससे अपनी प्राकृतिक गैस को अन्य देशों में बेचने की रूस की योजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

यू.के. ने रूस के पांच बैंकों और रूस के कई धनाढ्य लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सभी लोग रूस के राष्ट्रपति के गुट के हैं। हाई विजिलिबिलिटी स्पेड्स भी रूस से अन्यत्र भेजे जा रहे हैं। यूरोपीयन चैंपियंस लीग का फायनल सैंट पीटर्सबर्ग में होना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि रूस

# पुतिन ने इतिहास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में अब फायनल मैच नहीं हो सकता क्योंकि उसने रूस के संप्रभु देश पर हमला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था से ऑयल व नेचुरल गैस प्रमुख है तथा नैचुरल गैस सप्लाई में किसी तरह की बाधा रूस के अहम आर्थिक हितों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है जो उसके लिए कूटनीतिक वार्ताओं के कुछ अवसर उपलब्ध करवा रहे थे।

इसके साथ ही जर्मनी ने रूस से मध्य यूरोप तक जा रही नॉर्ड स्ट्रीम-2, पाइप लाइन में नैचुरल गैस की जरूरी सप्लाई रोक दी है। इससे अपनी प्राकृतिक गैस को अन्य देशों में बेचने की रूस की योजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

यू.के. ने रूस के पांच बैंकों और रूस के कई धनाढ्य लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सभी लोग रूस के राष्ट्रपति के गुट के हैं। हाई विजिलिबिलिटी स्पेड्स भी रूस से अन्यत्र भेजे जा रहे हैं। यूरोपीयन चैंपियंस लीग का फायनल सैंट पीटर्सबर्ग में होना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि रूस

सुनने को मिल रही है तथा वह पूरी तरह संतस एवं चबराई हुई है। वहीं राहुल गांधी की भी यही स्थिति है तथा ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस के अंकों को स्पर्श कर सकेगी। लेकिन कांग्रेस को तो पहले से ही पतली हालत थी लेकिन, जहाँ तक कुल 403 सीटों में से 327 के आँकड़े को बचाये जाने के लिहाज से तो भाजपा बहुत कुछ खेने की स्थिति में दिखाई दे रही है।

अचानक ही यूक्रेन की स्थिति ज्यादा गंभीर लगने लगी है और रूस के शक्ति प्रदर्शन से यह और बिगड़ सकता है।

रूस द्वारा यूक्रेन के दो विखंडित प्रांतों दनयन्स्क और लुहान्स्क को पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से यूरोप में आशंका का माहौल है और एक प्रकार का सीमित युद्ध शुरू हो सकता है।